



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 381] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 30, 2019/कार्तिक 8, 1941
No. 381] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 30, 2019/KARTIKA 8, 1941

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 22 अक्टूबर, 2019

सं. टीएमपी/25/2019-वीओसीपीटी.— महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, सीपोर्ट शिपिंग प्रा. लि. (एसएसपीएल) से परिचालक अर्थात् एसएसपीएल के नाम से राजस्व हिस्सेदारी आधार पर 10 वर्षों की अवधि के लिए बिजली से चलने वाले मोबाइल रबड़ टायर वाले होपरों के डिजाइन, आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण, शुरुआत तथा अनुरक्षण के लिए उसके दरमानों की अधिसूचना के लिए प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएमपी/25/2019-वीओसीपीटी

सीपोर्ट शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड

आवेदक

कोरम:

- (i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियम, सदस्य (वित्त)
(ii). श्री रजत सचर, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(अक्टूबर 2019 के 10 वें दिन पारित)

यह मामला सीपोर्ट शिपिंग प्रा. लि. (एसएसपीएल) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है जिसमें परिचालक अर्थात् एसएसपीएल के नाम से राजस्व हिस्सेदारी आधार पर 10 वर्षों की अवधि के लिए मोबाइल रबड़ टायर वाले बिजली से परिचालित होने वाले होपरों के डिजाइन, आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण, शुरुआत तथा अनुरक्षण के लिए उसके दरमानों (एसओआर) की अधिसूचना के बारे में है।

2. इस प्राधिकरण ने अपने आदेश सं. टीएमपी/60/2016-वीओसीपीटी दिनांक 16 दिसंबर 2016 द्वारा पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) द्वारा जारी किए गए 2013 के संदर्भ प्रशुल्क दिशानिर्देशों के अधीन बर्थ सं. III और IV में मोबाइल रबड़ टायर वाली बिजली-परिचालित 120 टन होपर के माध्यम से कार्गो की निकासी के लिए कार्गो ग्रहस्तन प्रभार अनुमोदित किए थे।

3.1. एसएसपीएल ने अपने पत्र दिनांक 08 मई 2019 द्वारा सूचित किया था कि वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास (वीओसीपीटी) ने लाइसेंस करार के अनुसार राजस्व हिस्सेदारी मॉडल के अधीन 10 वर्षों की अवधि के लिए उक्त परियोजना के लिए लाइसेंस प्रदान किया था। होपरों का वाणिज्यिक परिचालन 13 अप्रैल 2018 से शुरू हुआ था। तब से वे पत्तन के नियमित रूप से मासिक राजस्व हिस्सेदारी की अदायगी कर रहे हैं।

3.2. एसएसपीएल ने अपने पत्र दिनांक 8 मई 2019 द्वारा 01 अप्रैल 2019 से प्रसारित की जाने वाली दर के लिए एसएसपीएल के नाम से एसओआर की अधिसूचना के लिए प्रस्ताव भी जमा किया था। होपर के माध्यम से कार्गो प्रहस्तन प्रभारों के संबंध में एसएसपीएल द्वारा किए गए मुख्य निवेदन निम्नलिखित हैं:-

- (i). प्रशुल्क अधिकतम सीमाएं 01 जनवरी 2016 और प्रासंगिक वर्ष के 01 जनवरी के बीच आने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भिन्नता के 60 प्रतिशत की सीमा तक ही मुद्रास्फीति से सूचकांकित की जाएगी। प्रशुल्क अधिकतम सीमाओं का ऐसा स्वतः समायोजन प्रत्येक वर्ष किया जाएगा और समायोजित प्रशुल्क सीमाएं आगामी वर्ष के 01 अप्रैल से लागू होंगी।
- (ii). टीएमपी ने, प्रशुल्क नीति 2018 के खंड 2.8 और 2.9 के अनुसार, अपने पत्र सं. टीएमपी/12/2019-विविध दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए मौजूदा एसओआर पर 2.56 प्रतिशत का सूचकांकन कारक अनुमोदित किया था।
- (iii). उपर्युक्त पत्र के अनुसार, एसएसपीएल ने इस प्राधिकरण से अनुरोध किया था कि दिसंबर 2016 आदेश में अनुमोदित संदर्भ प्रशुल्क पर 2.56 प्रतिशत सूचकांकन कारक लागू करते हुए निम्नलिखित सूचकांकित दर अनुमोदित की जाए:

घटक	दर प्रति मी.ट. (रु. में)	
	विदेशी	तटीय
शुष्क बल्क कार्गो	16.97	10.18

3.3. एसएसपीएल ने अपने प्रस्ताव में वीओसीपीटी पत्र दिनांक 03 दिसंबर 2018 की प्रतिलिपि संलग्न की थी जिसमें वीओसीपीटी ने कहा था कि मैं एसएसपीएल ने राजस्व हिस्सेदारी माडल के अधीन लाइसेंस आधार पर शुष्क बल्क कार्गो के प्रहस्तन के लिए वीओसीपीटी में बिजली से चलने वाले मोबाइल खड़ टायरों वाले 8 होपर तैनात किए थे। वीओसीपीटी के उक्त पत्र में कहा गया है कि होपरों का परिचालन 13 अप्रैल 2018 से शुरू हुआ था और प्रदर्शन संतोषजनक पाया गया है। तथापि, धूल-उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए फ्लैक्स-फ्लैप प्रणाली 8 में से 7 होपरों में अभी संस्थापित की जानी है।

3.4. इस प्रकार, एसएसपीएल ने अनुरोध किया है कि होपर के माध्यम से प्रहस्तन के लिए कार्गो प्रहस्तन प्रभारों हेतु 01 अप्रैल 2019 से शुरू वर्ष 2019-20 के लिए उसके नाम से प्रस्तावित दरमान के लिए जरूरी अधिसूचना जारी की जाए ताकि इससे एसएसपीएल ये प्रभार 01 अप्रैल 2019 से उपयोक्ताओं से संग्रहीत कर सके।

4. एसएसपीएल ने अपने ईमेल दिनांक 14 मई 2019 द्वारा मसौदा एसओआर तथा कार्यनिष्पादन मानक भी भेजे थे।

5.1. प्रस्तावित एसओआर का अवलोकन करने पर, यह देखा गया था कि एसएसपीएल द्वारा लागू किया गया सूचकांकन कारक सही नहीं था। उपर्युक्त के मद्देनजर, एसएसपीएल से अनुरोध किया गया था कि हमारे पत्र दिनांक 12 जून 2019 द्वारा मांगी गई निम्नलिखित सूचना के साथ शोधित एसओआर तत्काल भेजे।

- (i). चूंकि एसएसपीएल ने 13 अप्रैल 2018 से वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया था, इसलिए आधार वर्ष 2016 के लिए सही वार्षिक सूचकांकन वर्ष 2017-18 के लिए घोषित सूचकांकन कारक होगा जोकि 1.20 प्रतिशत है।

उक्त सूचकांकन लागू करते हुए दर निम्नवत् होगी:

शुष्क बल्क कार्गो के लिए आदेश सं. टीएमपी/60/2016-वीओसीपीटी दिनांक 16 दिसंबर 2016 में अनुमोदित आधार दर (प्रति मी.ट.) (रु. में)		वर्ष 2017-18 के लिए 1.2 प्रतिशत और वर्ष 2018-19 (1-4-2018 से 31-7-2018) के लिए शून्य लागू करते हुए सूचकांकित दर (प्रति मी.ट.) (रु. में)		वर्ष 2018-19 के एक भाग के लिए लागू
विदेशी	तटीय	विदेशी	तटीय	13.4.2018 (परिचालन की शुरुआत) से 31.7.2018
16.21	9.73	16.40	9.84	

- (ii). वर्ष 2018-19 के शेष भाग अर्थात् 01 अगस्त 2018 से 31 मार्च 2019 और अनुवर्ती वर्षों के लिए वार्षिक सूचकांकन में एसएसपीएल के नाम से अधिसूचित इस संबंध में एसओआर में निर्धारित टिप्पणी के मद्देनजर स्वतः ही वृद्धि होती जाएगी। तदनुसार, दर निम्नवत् होगी (यह स्वचालित सूचकांकन के कार्यान्वयन के संबंध में एसएसपीएल की सूचना के लिए है):

वर्ष	इस प्राधिकरण द्वारा घोषित सूचकांकन कारक	सूचकांकित दर प्रति मी.ट. (रु. में)	
		विदेशी	तटीय
2018.19 (01.08.2018 से 31.03.2019)	2.07%	16.73	10.04
2019.20	2.56%	17.15	10.29

- (iii). वह प्रशुल्क व्यवस्था दर्शाये जिसके अधीन एसएसपीएल ने परिचालन के शुरू होने की तारीख अर्थात् 13 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिए प्रशुल्क संग्रहीत किया था।

- (iv). स्वतंत्र अभियंता से कार्य पूर्ण होने का प्रमाणपत्र जमा नहीं किए जाने का कारण बतायें।

- (v). प्रशुल्क आदेश सं. टीएमपी/60/2016-वीओसीपीटी में यथा अनुमोदित शर्तों के साथ (आधार दर पर) एसओआर प्रस्तुत करें।

5.2. प्रतिसाद में, एसएसपीएल ने पत्र दिनांक 18 जून 2019 द्वारा कहा था कि लाइसेंस करार के अधीन, लाइसेंसदाता अर्थात् वीओसीपीटी द्वारा कोई स्वतंत्र अभियंता नियुक्त नहीं किया गया था और इसलिए इस परियोजना के लिए स्वतंत्र अभियंता से कार्यपूर्ण प्रमाणपत्र लागू नहीं है। जहां तक शर्तों के साथ एसओआर का संबंध है, एसएसपीएल ने कहा था कि यह हमारे ईमेल दिनांक 14 मई 2019 द्वारा पहले ही जमा किया जा चुका है।

6. एसएसपीएल के प्रस्ताव दिनांक 8 मई 2019 और 18 जून 2019 की एक-एक प्रतिलिपि वीओसीपीटी को उसकी टिप्पणियों के लिए अग्रप्रेषित की गई थी और अनुस्मारक दिनांक 28 जून 2019 और 05 जुलाई 2019 भेजे गए थे। वीओसीपीटी ने अपने ईमेल दिनांक 17 जुलाई 2019 द्वारा प्रतिसाद दिया था। वीओसीपीटी के निवेदनों को नीचे सारबद्ध किया गया है—

परियोजना 13 अप्रैल 2018 से शुरू हुई थी। लाइसेंस करार के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, विषय प्रस्ताव के लिए स्वतंत्र अभियंता द्वारा कार्यपूर्ण प्रमाणपत्र जारी किए जाने की आवश्यकता नहीं है। पत्तन अधिकारियों की एक समिति ने कार्य का निरीक्षण किया था और प्रतिवेदन जमा किया था। प्रतिवेदन के आधार पर, कार्यपूर्ण प्रमाणपत्र दिनांक 03 दिसंबर 2018 (प्रतिलिपि संलग्न) जारी किया गया था। कंपनी ने फ्लैक्स फ्लैप प्रणाली संस्थापित करने के लिए सितंबर 2019 तक का समय प्रदान किए जाने का अनुरोध किया था।

मै. सीपोर्ट शिपिंग प्रा. लि. के नाम से विषय परियोजना के लिए एसओआर अधिसूचित किए जाने के एसएसपीएल के प्रस्ताव पर विचार किया जाए।

7.1. अप्रकट प्रशुल्क के निर्धारण के लिए 2008 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.9.1. में विनिर्दिष्ट किया गया है कि निजी परिचालक एमपीटी अधिनियम की धारा 48 के अधीन और 2008 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.9.2. के अनुसार यथा अपेक्षित वाणिज्यिक परिचालनों की शुरुआत से पहले उसके परिचालनों के लिए लागू अधिकतम दरों वाले एसओआर की अधिसूचना के लिए इस प्राधिकरण का रुख करेगा, इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाने वाला एसओआर पत्तन के लिए निर्धारित प्रशुल्क सीमाओं के अनुसार होगा और खंड 2.8 में स्पष्ट किए गए सूचकांकन के अधीन बोली दस्तावेज में शामिल किया जाएगा। ऐसा एसओआर और शर्तों के विवरण महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 द्वारा यथा अपेक्षित भारत के राजपत्र में इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

7.2. जबकि 2008 के अप्रकट प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.9.1 में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया गया है कि वाणिज्यिक परिचालन के शुरू होने से पहले, निजी परिचालक महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 48 के अधीन यथा अपेक्षित एसओआर की अधिसूचना के लिए इस प्राधिकरण का रुख करेगा, 2013 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

7.3. महापत्तन न्यास अधिनियम (एमपीटी) अधिनियम, 1963 की धारा 42(4) के साथ पठित धारा 48 के अनुसार, सेवाएँ प्रदान करने के लिए महापत्तन न्यासों द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित एसओआर के आधार पर प्रशुल्क की वसूली कर सकता है। ऐसी स्थिति में, एमपीटी अधिनियम, 1963 की धारा 42 (3) के अधीन महापत्तन न्यास द्वारा प्राधिकृत और 2013 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के अधीन शासित बीओटी परिचालकों को परिचालनों की शुरुआत से काफी पहले अपने नाम में अधिसूचित सूचकांकित एसओआर प्राप्त करने की जरूरत होगी।

7.4. 2013 के संदर्भ प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 4.2 के अनुसार, प्रशुल्क अधिकतम सीमाओं को मुद्रास्फीति से सूचकांकित किया जाता है परंतु 1 जनवरी 2008 और प्रासंगिक वर्ष के 1 जनवरी के बीच आने वाले डब्ल्यूपीआई में भिन्नता के 60 प्रतिशत की सीमा तक ही, और समायोजित प्रशुल्क प्रासंगिक वर्ष के 1 अप्रैल से आगामी वर्ष के 31 मार्च तक लागू होगा।

7.5. इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएमपी/60/2016-वीओसीपीटी दिनांक 16 दिसंबर 2016 द्वारा अनुमोदित वीओसीपीटी में बर्थ सं. 3 और 4 पर बिजली से चलने वाले मोबाइल रबड़ टायर वाले होपों के माध्यम से जलयान से ट्रकों पर सीधे उतराई तक कार्गो के स्थानांतरण के लिए संदर्भ प्रशुल्क में 3 सामान्य टिप्पणियों के अधीन टिप्पणी (i) के अनुसार, प्रशुल्क सीमाएं 1 जनवरी 2016 और प्रासंगिक वर्ष के 1 जनवरी के बीच आने वाले डब्ल्यूपीआई में भिन्नता के 60 प्रतिशत की सीमा तक मुद्रास्फीति से सूचकांकित की जाएंगी।

8. संदर्भ प्रशुल्क के लिए आधार वर्ष और वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए तदनुकूली वार्षिक वृद्धि कारक इस प्राधिकरण द्वारा घोषित किए गए हैं और वीओसीपीटी सहित सभी महापत्तन न्यासों को संप्रेषित किया गया था और उन्हें नीचे भी दिया गया है:

वर्ष	2013 दिशानिर्देशों के अधीन इस प्राधिकरण द्वारा घोषित वार्षिक सूचकांकन कारक (डब्ल्यूपीआई के 60 प्रतिशत की दर से)
2014.15	3.78%
2015.16	2.29%
2016.17	शून्य
2017.18	1.20%
01.04.18 जव 31.07.18	शून्य
01.08.18 जव 31.03.19	2.07%
2019.2020	2.56%

इस प्रकार संक्षेप में, अपने नाम से एसओआर की अधिसूचना के लिए 13 अप्रैल 2018 को वाणिज्यिक परिचालन की शुरुआत के बाद आया है और वीओसीपीटी ने वाणिज्यिक परिचालन के शुरू होने की तारीख अर्थात् 13 अप्रैल 2018 से एसएसपीएल के नाम से एसओआर में अधिसूचना के लिए अनुरोध भी किया था।

9.1. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है:—

- (i). इस प्राधिकरण ने वीओसीपीटी में बर्थ सं. 3 और 4 पर बिजली से चलने वाले मोबाइल रबड़ टायर वाले होपों के माध्यम से जलयान से ट्रकों पर सीधे उतराई तक कार्गो के स्थानांतरण के लिए वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास (वीओसीपीटी) द्वारा दाखिल किए गए प्रस्ताव कि आधार पर संदर्भ प्रशुल्क निर्धारित करते हुए एक आदेश सं. टीएमपी/60/2016-वीओसीपीटी दिनांक 16 दिसंबर 2016 पारित किया था। उक्त आदेश भारत का राजपत्र असाधारण में 12 जनवरी 2017 को राजपत्र सं. 13 द्वारा अधिसूचित किया गया था।
- (ii). वीओसीपीटी ने मै. सीपोर्ट शिपिंग प्रा. लि. (एसएसपीएल) को 10 वर्षों की अवधि के लिए लाइसेंस धार पर उक्त परियोजना प्रदान की थी और वीओसीपीटी ने 10 वर्षों की अवधि के लिए 05 अप्रैल 2017 को एसएसपीएल के साथ लाइसेंस करार किया था।
- (iii). महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 42 (4) के साथ पठित धारा 48 के अनुसार, सेवाएं प्रदान करने के लिए एमपीटी द्वारा प्राधिकृत कोट व्यक्ति इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित दरमानों (एसओआर) के आधार पर प्रशुल्क वसूल कर सकता है। ऐसी स्थिति में, एमपीटी अधिनियम, 1963 की धारा 42 (3) के अधीन महापत्तन न्यास द्वारा प्राधिकृत और 2013 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के अधीन शासित बीओटी परिचालकों को परिचालनों की शुरुआत से काफी पहले अपने नाम में अधिसूचित सूचकांकित एसओआर प्राप्त करने की जरूरत होगी। एसएसपीएल ने वाणिज्यिक परिचालन के शुरू होने के बाद अपने नाम से एसओआर अधिसूचित करने के लिए 13 अप्रैल 2018 को इस प्राधिकरण का रुख किया था।

- (iv). एसएसपीएल द्वारा यथा प्रतिवेदित, परिचालक ने वाणिज्यिक परिचालन 13 अप्रैल 2018 से शुरू किए थे। एसएसपीएल द्वारा अंग्रेषित वीओसीपीटी के पत्र दिनांक 03 दिसंबर 2018 की प्रतिलिपि में कहा गया है कि होपरों ने 13 अप्रैल 2018 से परिचालन शुरू किए थे और प्रदर्शन संतोषजनक पाया गया है। वीओसीपीटी ने बताया है कि लाइसेंस करार के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, पत्तन अधिकारियों की एक समिति ने एसएसपीएल द्वारा तैनात 8 होपरों का निरीक्षण किया था और पाया था कि प्रदर्शन संतोषजनक है। धूल उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए फ्लैक्स फ्लैप प्रणाली के सितंबर 2019 तक संस्थापित होने की उम्मीद थी। पत्तन ने पुष्टि की है कि लाइसेंसधारी ने 13 अप्रैल 2018 से परिचालन शुरू कर दिया था। वीओसीपीटी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चूंकि प्रणाली 13 अप्रैल 2018 से परिचालन के लिए इस्तेमाल की गई है, इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले प्रशुल्क के लागू होने की तारीख को तदनुसार 13 अप्रैल 2018 सुविचारित किए जाने की जरूरत है।
- (v). एसएसपीएल ने अपने प्रस्ताव में एसओआर की अधिसूचना 1 अप्रैल 2019 से किए जाने की मांग की थी। यदि संदर्भ प्रशुल्क 1 अप्रैल 2019 से अधिसूचित किया जाता है तो परिचालनों के शुरू होने की तारीख अर्थात् 13 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक एसएसपीएल द्वारा संग्रहीत प्रशुल्क के लिए इस प्राधिकरण का कोई अनुमोदित नहीं होगा। संविधि के अनुसार, पत्तन द्वारा प्राधिकृत परिचालक इस प्राधिकरण द्वारा एसओआर की अधिसूचना के बाद ही अपने द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए प्रशुल्क संग्रहीत कर सकता है। एसएसपीएल ने अपने नाम से एसओआर की अधिसूचना के लिए अप्रैल 2018 में इस प्राधिकरण का रुख नहीं किया था। अब इसने अपने नाम से एसओआर की अधिसूचना के लिए मसौदा एसओआर के साथ प्रस्ताव मई 2019 में दाखिल किया है। तथापि, वीओसीपीटी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि चूंकि प्रणाली परिचालन के लिए 13 अप्रैल 2018 से इस्तेमाल की गई है, इसलिए प्रशुल्क के लागू होने की तारीख तदनुसार 13 अप्रैल 2018 सुविचारित की जाए। ऐसी स्थिति में, यह प्राधिकरण इस प्राधिकरण द्वारा घोषित लागू डब्ल्यूपीआई वृद्धि के अधीन आदेश दिनांक 16 दिसंबर 2016 में अनुमोदित संदर्भ प्रशुल्क लेते हुए एसओआर की अधिसूचना के लिए एसएसपीएल के प्रस्ताव पर कार्यवाही करने के लिए प्रवृत्त है। ऊपर बताई गई स्थिति के मद्देनजर, और लाइसेंसदाता पत्तन द्वारा यथा अनुशंसित, इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित सूचकांकित एसओआर एसएसपीएल द्वारा वाणिज्यिक परिचालन शुरू किए जाने की तारीख अर्थात् 13 अप्रैल 2018 से लागू किया जाएगा।
- (vi). (क). आदेश दिनांक 16 दिसंबर 2016 द्वारा निर्धारित संदर्भ प्रशुल्क के सूचकांकन के संदर्भ में, यह उल्लेखनीय है कि एसएसपीएल ने, अपना मसौदा एसओआर दाखिल करते समय, वर्ष 2019-20 के लिए इस प्राधिकरण द्वारा घोषित 2.56 प्रतिशत का वृद्धि कारक लागू किया था। इस संबंध में, यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएमपी/60/2016-वीओसीपीटी दिनांक 16 दिसंबर 2016 द्वारा पारित संदर्भ प्रशुल्क आदेश के पैरा 11(xii) और संदर्भ प्रशुल्क अनुमोदित करते हुए एसओआर में सामान्य टिप्पणी सं. (i), बताया गया है कि प्रशुल्क सीमा 1 जनवरी 2016 और प्रासंगिक वर्ष के 1 जनवरी के बीच आने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के 60 प्रतिशत की सीमा तक मुद्रास्फीति से सूचकांकित किया जाना है। सामान्य टिप्पणी में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि डब्ल्यूपीआई वृद्धि के लिए आधार वर्ष 1 जनवरी 2016 होगा।
- (ख). ऐसी स्थिति में, 13 अप्रैल 2018 को सूचकांकित एसओआर पर पहुंचने के लिए लागू वृद्धि कारक वर्ष 2017-18 के लिए 1.2 प्रतिशत है; 1 अप्रैल 2018 से 31 जुलाई 2018 अवधि के लिए शून्य और 1 अगस्त 2018 से 31 मार्च 2019 अवधि के लिए 2.07 है। इसके अलावा, कार्यान्वयन सुगम बनाने के लिए और चूंकि वर्ष 2019-20 पहले ही शुरू हो चुका है, 2.56 प्रतिशत का लागू सूचकांकन कारक लागू करते हुए वर्ष 2019-20 के लिए लागू सूचकांकित दर भी एसएसपीएल के नाम से अधिसूचित एसओआर में निर्धारित की गई है। अनुवर्ती वर्षों के लिए, प्रशुल्क 2013 के संदर्भ प्रशुल्क दिशानिर्देशों के अधीन प्रतिवर्ष इस प्राधिकरण द्वारा घोषित किए जाने वाले जनवरी 2019 के अनुसार आधार वर्ष के साथ डब्ल्यूपीआई के 60 प्रतिशत की दर से सूचकांकन कारक लागू करते हुए स्वतः सूचकांकित किया जाएगा। आदेश दिनांक 16 दिसंबर 2016 में अनुमोदित सामान्य टिप्पणी में निर्धारित प्रशुल्क में स्वतः वृद्धि के संबंध में एसएसपीएल द्वारा प्रस्तावित अनुसूची (2) के लिए सामान्य टिप्पणी सं. (i) को उस सीमा तक थोड़ा संशोधित किया गया है।
- तदनुसार, इस प्राधिकरण द्वारा घोषित सही सूचकांकन कारक लागू करते हुए, एसएसपीएल के नाम से अधिसूचित सूचकांकित प्रशुल्क निम्नलिखित है:

दर/मी.ट. (रु. में)

13 अप्रैल 2018 से 31 जुलाई 2018 तक		1 अगस्त 2018 से 31 मार्च 2019 तक		वर्ष 2019-20 के लिए	
वर्ष 2017-18 के लिए 1.2 प्रतिशत और वर्ष 2018-19 (1-4-2018 से 31-7-2018 तक) के लिए शून्य लागू करते हुए सूचकांकित दर (रु. में प्रति मी.ट.)		2.07 प्रतिशत सूचकांकन कारक लागू करते हुए 1 अगस्त 2018 से 31 मार्च 2019 तक लागू की जाने वाली सूचकांकित दर		2.56 प्रतिशत सूचकांकन लागू करते हुए सूचकांकित दर	
विदेशी	तटीय	विदेशी	तटीय	विदेशी	तटीय
16.40	9.84	16.74	10.05	17.17	10.30

- (vii). आदेश दिनांक 16 दिसंबर 2016 के एसओआर में यथा अनुमोदित दरों के कार्यान्वयन को शासित करने वाली सभी अन्य शर्तें निम्नलिखित के अधीन बनाये रखी गई हैं:

इस प्राधिकरण ने तटीय कार्गो/कंटेनर के लिए रियायती प्रमारों की वसूली के संबंध में वीओसीपीटी द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण पर महानिदेशक (डीजी) शिपिंग की अनुशंसाओं के आधार पर एक आदेश सं. टीएमपी/53/2015-वीओसीपीटी दिनांक 29 सितंबर 2015 पारित किया था। उक्त आदेश में अनुमोदित प्रावधानों में बाद में आदेश सं. टीएमपी/53/2015-वीओसीपीटी दिनांक 26 नवंबर 2015 द्वारा संशोधन किया गया था। उक्त पारित आदेश सभी महापत्तन न्यासों द्वारा सामान्य अंगीकरण के लिए है। उक्त आदेश के बाद, डीजी शिपिंग ने अपने पत्र सं. एसडी-9 चार्ट(309)/2016 दिनांक 20 मई 2016 द्वारा 26 नवंबर 2015 आदेश में अनुमोदित प्रावधान पर आगे स्पष्टीकरण जारी किया था। इस प्राधिकरण ने तदनुसार आदेश दिनांक 26 नवंबर 2015 के पैरा 9क(ii) और 10(ii) में निर्धारित प्रावधान में थोड़ा संशोधन करते हुए एक स्पष्टीकरण आदेश पारित किया था। उक्त आदेश में इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संशोधित प्रावधान जोकि कार्गो प्रहस्तन प्रमारों के संबंध में एसएसपीएल के मामले में प्रासंगिक पाये गए हैं, को सामान्य निबंधन एवं शर्तों के अधीन प्रस्तावित टिप्पणी सं. (ii) के स्थान पर टिप्पणी सं. (ii) के रूप में तदनुसार अद्यतन किया गया है। इसके अलावा, तटीय रियायत के लिए जो कुछ कार्गो मर्चें हकदार नहीं हैं उन्हें छोड़कर जलयान से तट और तट से याई आवागमन के लिए तटीय रियायत की अनुप्रयोज्यता के संबंध में सामान्य शर्तें निर्धारित की गई हैं। यह सरकार की तटीय रियायत नीति के अनुसार है और सभी महापत्तन न्यासों तथा बीओटी परिचालकों के एसओआर में एकसमान रूप से निर्धारित की गई है।

- 9.2. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से तथा समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण वीओसीपीटी में परिचालन कर रहे एसएसपीएल के नाम से 10 वर्षीय अवधि आधार के लिए लाइसेंस आधार पर बर्थ सं. 3 और 4 पर बिजली से चलने वाले मोबाइल रबड़ टायर वाले होपरों के माध्यम से जलयान से ट्रकों पर सीधे उतराई तक कार्गो के स्थानांतरण के लिए एसओआर तथा कार्यनिष्पादन मानकों की अधिसूचना संलग्न अनुबंध-I और II रूप में अनुमोदित करता है।
- 9.3. एसएसपीएल के लिए अधिसूचित एसओआर वीओसीपीटी में एसएसपीएल द्वारा परिचालनों की शुरुआत की तारीख अर्थात् 13 अप्रैल 2018 से लागू किया माना जाएगा।
- 9.4. टर्मिनल में वाणिज्यिक परिचालन के दौरान, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर, एसएसपीएल को यह निदेश दिया जाता है कि वीओसीपीटी के माध्यम से इस प्राधिकरण को एक रिपोर्ट जमा की जाएगी जिसमें पूर्व तीन महीनों के दौरान भौतिक कार्यनिष्पादन होगा और वित्तीय वर्ष की समाप्ति होने के दो महीनों के भीतर भौतिक तथा वित्तीय कार्यनिष्पादन को शामिल करते हुए एक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष के अंत में जमा की जाएगी।
- 9.5. दिशानिर्देशों के खंड 3.8.5 के अनुसार, एसओआर तथा शर्तों के विवरण के संबंध में कोई स्पष्टीकरण अथवा निर्वचन का कोई प्रश्न उठता है तो यह मामला प्राधिकरण को भेजा जाएगा और इस संबंध में इसका निर्णय परिचालक पर बाध्यकारी होगा।
- 9.6. लाइसेंसधारी से यह उम्मीद की जाती है कि कम से कम बोली दस्तावेज/लाइसेंस करार में दिए गए कार्यनिष्पादन मानदंडों की दर से कार्यनिष्पादन किया जाए।
- 9.7. लाइसेंसधारी का वास्तविक कार्यनिष्पादन इस प्राधिकरण द्वारा मॉनीटर किया जाएगा। यदि सेवा की गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो यह प्राधिकरण ऐसे आरोप की जांच कर सकता है और अपने निष्कर्ष वीओसीपीटी को अग्रेषित करेगा। यदि परिचालक के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जानी होगी तो वीओसीपीटी प्रासंगिक लाइसेंस करार के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू करेगा।

टी.एस. बालासुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
[विज्ञापन III/4/असा./264/19]

अनुबंध-I

सीपोर्ट शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड

वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास में बर्थ सं. 3 और 4 पर बिजली से चलने वाले मोबाइल रबड़ टायर वाले होपरों के माध्यम से जलयान से ट्रकों पर सीधे उतराई के लिए कार्गो के स्थानांतरण के लिए दरमान।

अध्याय 1 – परिभाषाएँ और सामान्य निबंधन एवं शर्तें

1.1. परिभाषाएँ – सामान्य

इस दरों के मान में जब तक संदर्भ के अनुसार अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, निम्नलिखित परिभाषाएँ लागू होंगी:

- (i). **‘तटीय पोत’** का अभिप्राय किसी ऐसे पोत से होगा जो भारत में किसी पत्तन अथवा स्थान से भारत में स्थित किसी अन्य पत्तन अथवा स्थान के बीच व्यापार में संलग्न है और जिसके पास सक्षम प्राधिकारी/महानिदेशक शिपिंग द्वारा जारी वैध तटीय लाइसेंस है।
- (ii). **‘विदेशगामी पोत’** का अभिप्राय तटीय पोत से भिन्न किसी अन्य पोत के लिए होगा।
- (iii). **“पत्तन”** अर्थात् वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास होगा।
- (iv). **‘पाली’** का अभिप्राय पत्तन कर्मचारियों पर लागू आठ घंटों की पाली से होगा।
- (v). **“प्रतिदिन”** अर्थात् एक केलेंडर दिवस अथवा उसका भाग होगा।
- (vi). **“टीएएमपी”** अर्थात् महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 47क के अधीन गठित महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण होगा।
- (vii). **“टन”** अर्थात् एक मीट्रिक टन अथवा 1000 किलोग्राम होगा।

1.2. सामान्य निबंधन एवं शर्तें:

- (i). सीमाशुल्क या नौवहन महानिदेशक द्वारा उसके प्रमाणन में यथा वर्णित पोत की प्रास्थिति पोत-संबद्ध प्रभार लगाने के प्रयोजनार्थ ‘तटीय’ अथवा ‘विदेशगामी’ श्रेणी के रूप में उसके वर्गीकरण के लिए निर्णायक कारक होगी तथा कार्गो की प्रकृति अथवा उसके मूल स्थान की इस प्रयोजनार्थ कोई संगतता नहीं होगी।
- (ii). **रियायती तटीय दर तथा विदेशी दर पर पोत संबंधित प्रभारों (वीआरसी) की वसूली हेतु मानदंड**
 - (क). ऐसे परिवर्तन के मामलों में लदान करने वाले पत्तन द्वारा पोत के तटीय सामग्रियों का लदान प्रारंभ करने के समय से तटीय दरें वसूल की जाएंगी।
 - (ख). ऐसे परिवर्तन के मामले में तटीय दरें केवल तब तक प्रभार्य होंगी, जब तक पोत तटीय कार्गो का उतराई प्रचालन पूरा करता है, उसके तत्काल बाद विदेशगामी दरें उतराई पत्तन द्वारा वसूल की जाएंगी।
 - (ग). महानिदेशक, नौवहन से प्राप्त तटीय लाइसेंस वाले नियत भारतीय तटीय पोतों के लिए तटीय दरों के हकदार होने के लिए अन्य दस्तावेज की अपेक्षा नहीं होगी।
- (iii). रियायती तटीय दर पर कार्गो संबंधित प्रभारों (सीआरसी) की वसूली हेतु मानदंड

- (क). 'विश्वव्यापी तथा तटीय' परिचालन के लिए जारी किए गए सामान्य ट्रेडिंग लाइसेंस वाले विदेशगामी भारतीय पोत प्रहस्तन प्रमारों के मामले में अर्थात् जलयान से तट स्थानांतरण और निम्नलिखित परिदृश्य में घाटशुल्क सहित घाट से/को भंडारण यार्ड और विलोमतः तटीय दरें लागू की जाएंगी:
- (i). तटीय चालन में परिवर्तित और किसी भारतीय पत्तन से तटीय कार्गो की दुलाई करना और किसी अन्य भारतीय पत्तन के लिए गंतव्यित करना।
- (ii). तटीय चालन में * अपरिवर्तित परन्तु किसी भारतीय पत्तन से तटीय कार्गो की दुलाई करना और किसी अन्य भारतीय पत्तन के लिए गंतव्यित करना।
- * केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड का परिपत्र सं. 15/2002-सी. दिनांक 25 फरवरी 2002 बिना किसी सीमाशुल्क परिवर्तन के भारतीय ध्वज वाले विदेशगामी पोतों में एक भारतीय पत्तन से भारत में दूसरे पत्तन तक तटीय कार्गो की दुलाई की अनुमति देता है।
- (ख). जहाजरानी महानिदेशालय द्वारा जारी किए गए विनिर्दिष्ट अवधि अथवा नौप्रस्थान के लिए लाइसेंस और सीमाशुल्क परिवर्तन आदेश के आधार पर तटीय चालन में परिवर्तित विदेशी ध्वज वाले पोत के मामले में, किसी भारतीय पत्तन से लादा गया तथा किसी अन्य भारतीय पत्तन के लिए गंतव्यित तटीय कार्गो/कंटेनर तटीय कार्गो/कंटेनर के लिए लागू दर पर वसूल किया जाएगा।
- (iv). (क). ताप कोयला से इतर तटीय कार्गो के लिए कार्गो संबंधित प्रभार सामान्य कार्गो संबंधित प्रभारों के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।
- (ख). कार्गो संबंधित प्रभारों के मामले में, रियायती दरें जलयान तट स्थानांतरण और घाटशुल्क सहित घाट से भंडारण यार्ड/भंडारण यार्ड से घाट तक स्थानांतरण के लिए सभी प्रासंगिक प्रहस्तन प्रभारों पर वसूल की जाएंगी।
- (ग). किसी विदेशी पत्तन से कार्गो, जो भारतीय पत्तन 'ख' को अनुवर्ती पोतांतरण के लिए भारतीय पत्तन 'क' में पहुंचता है, उस पर उसकी तटीय यात्रा के लिए संगत रियायती प्रभार लगाए जाएंगे। अन्य शब्दों में, तटीय यात्रा करने के लिए अनुमत पोतों द्वारा भारतीय पत्तनों से/तक संवाहित कार्गो/कंटेनर इस रियायत के लिए अर्हक होंगे।
- (v). **विलंबित भुगतानों/वापसी अदायगियों पर ब्याज:**
- (क). प्रयोक्ता इस दरमान के अधीन किसी प्रभार के विलंबित भुगतानों पर दंडात्मक ब्याज की अदायगी करेगा। ब्याज की दर भारतीय स्टेट बैंक की प्रधान उधार दर से 2 प्रतिशत अधिक पर निर्धारित की जाएगी।
- (ख). इसी तरह, टर्मिनल विलंबित वापसियों पर दंडात्मक ब्याज की अदायगी करेगा। ब्याज की दर भारतीय स्टेट बैंक की प्रधान उधार दर से 2 प्रतिशत अधिक पर निर्धारित की जाएगी।
- (ग). वापसियों में विलंब सेवाओं के पूरा होने की तारीख अथवा उपयोक्ताओं से अपेक्षित दस्तावेजों के पेश किए जाने, जो भी बाद में हो, से 20 दिनों बाद से गिनती किया जाएगा। (टर्मिनल वापसी का दावा करने के लिए विशिष्ट दस्तावेज अवश्य निर्दिष्ट करेगा)।
- (घ). प्रयोक्ताओं द्वारा भुगतानों में विलंब की गणना टर्मिनल द्वारा बिल प्रेषित करने की तिथि के बाद 10 दिनों के बाद से की जाएगी। तथापि, यह प्रावधान उन मामलों पर लागू नहीं होगा, जहां भुगतान महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में यथाविनिर्दिष्ट सेवाएं प्राप्त करने/पत्तन न्यास की संपत्तियों का प्रयोग किए जाने से पूर्व किया जाना है तथा/अथवा जहां इस दरों के मान में प्रभारों के अग्रिम भुगतान की शर्त निर्धारित की गई है।
- (vi). सभी प्रभार प्रत्येक बिल के सकल जोड़ पर अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किए जाएंगे।
- (vii). जब तक वापसी योग्य राशि 100/- रुपये अथवा उससे अधिक न हो, कोई वापसी अदायगी नहीं की जाएगी। इसी प्रकार, परिचालक कोई अनुपूरक अथवा प्रभार अधीन बिल जारी नहीं करेगा, यदि परिचालक को देय राशि रु. 100/- अथवा कम हो।
- (viii). (क). दरों के मान में निर्धारित दरें उच्चतम स्तर की हैं, इसकी प्रकार, छूट तथा रियायतें न्यूनतम स्तर की हैं। परिचालक, यदि वह चाहे, निम्नतर दरें प्रभारित कर सकता है अथवा उच्चतर छूट एवं/अथवा रियायतें अनुमत कर सकता है।
- (ख). परिचालक, यदि वह चाहे, दरों के मान में निर्धारित दरों की प्रयोज्यता को शासित करने वाली निर्धारित शर्तों को युक्तिसंगत बना सकता है, यदि ऐसे यौक्तिकीकरण से प्रयोक्ता को प्रति यूनिट दर में राहत मिले तथा दरों के मान में निर्धारित यूनिट दरें उच्चतम स्तरों से अधिक न हों। तथापि, पत्तन न्यास सार्वजनिक रूप से ऐसे निम्नतर दरों को तथा/अथवा ऐसी दरों की प्रयोज्यता को शासित करने वाली शर्तों के यौक्तिकीकरण को अधिसूचित करेगा तथा ऐसे निम्नतर दरों तथा/अथवा ऐसी दरों की प्रयोज्यता शासित करने वाली शर्तों में आगे किन्हीं और परिवर्तनों को सार्वजनिक रूप से अधिसूचित करना जारी रखेगा, बशर्त कि नियत की गई नई दरें टीएएमपी द्वारा अधिसूचित दरों से अधिक नहीं होंगी।
- (ix). उपयोक्ता को परिचालक पर आरोप्य स्तर से अधिक विलंबों के लिए प्रभारों की अदायगी करने की आवश्यकता नहीं होगी।

2.

बर्थ सं. 3 और 4 में बिजली से चलने वाले मोबाइल रबड़ टायर वाले 120 टन होपर के माध्यम से कार्गो की निकासी के लिए कार्गो प्रहस्तन प्रभार:

दर प्रति मी.ट. में (रु. में)

क्र.सं.	घटक	परिचालनों की शुरुआत की तारीख अर्थात् 13 अप्रैल 2018 से 31 जुलाई 2018 तक दर		01 अगस्त 2018 से 31 मार्च 2019 तक दर		वर्ष 2019-20 के लिए दर	
		विदेशी	तटीय	विदेशी	तटीय	विदेशी	तटीय
1	शुष्क बल्क कार्गो	16.40	9.84	16.74	10.05	17.17	10.30

टिप्पणियाँ:

उपर्युक्त निर्धारित दर बर्थ सं. 3 और 4 पर बिजली से चलने वाले मोबाइल रबड़ टायर वाले होपों के माध्यम से जलयान से ट्रकों पर सीधे उतराई के लिए कार्गो के स्थानांतरण के लिए है।

3. सामान्य टिप्पणियाँ:

- (i). प्रशुल्क सीमाएं 1 जनवरी 2019 और प्रासंगिक वर्ष के 1 जनवरी के बीच आने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भिन्नता के 60 प्रतिशत की सीमा तक ही मुद्रास्फीति से सूचकांकित की जाएगी। प्रशुल्क सीमाओं का ऐसा स्वतः समायोजन प्रत्येक वर्ष किया जाएगा और समायोजित प्रशुल्क सीमाएं प्रासंगिक वर्ष के 1 अप्रैल से आगामी वर्ष के 31 मार्च तक लागू होंगी। प्रशुल्क में अगला स्वतः सूचकांकन 01 अप्रैल 2020 से होगा।
- (ii). उसी वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक वाणिज्यिक परिचालन की तारीख (सीओडी) से, प्रशुल्क को उस वर्ष के लिए प्रासंगिक सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क तक सीमित किया जाएगा, जोकि अधिकतम होगा। उपर्युक्त संदर्भ प्रशुल्क 2013 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के पैरा 2.2 में यथा दिए गए सूचकांकन के आधार पर प्रत्येक वर्ष स्वतः संशोधित किया जाएगा जोकि सम्पूर्ण लाइसेंस अवधि के लिए लागू होगा।
तथापि, लाइसेंसधारी आगामी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से कम से कम 90 दिन पहले प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क से ऊपर परिचालन के दूसरे वर्ष से आगे से कार्यनिष्पादन मानकों ('कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क') के साथ प्रशुल्क प्रस्तावित करने के लिए स्वतंत्र होगा। ऐसा कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क उस वित्तीय वर्ष के लिए सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क से 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और यह प्रशुल्क अधिकतम सीमा होगी। कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क आगामी वित्तीय वर्ष के पहले दिन से लागू होगा और सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए लागू रहेगा।
- (iii). टीएएमपी को प्रस्ताव लाइसेंस करार में यथा शामिल पिछले 12 महीनों अथवा परिचालन के प्रथम वर्ष में परिचालन के महीनों की वास्तविक संख्या, जैसी भी स्थिति हो, में कार्यनिष्पादन मानकों की उपलब्धि दर्शाते हुए परियोजना के रियायत करार के अधीन नियुक्त स्वतंत्र अभियंता से प्रमाणपत्र के साथ जमा किया जाएगा।
- (iv). प्रस्ताव प्राप्त होने पर, टीएएमपी 2013 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के पैरा 5 में यथा दिए गए अनुसार कार्यनिष्पादन मानकों की उपलब्धि पर, प्राप्ति से 7 दिनों के भीतर, महापत्तन न्यासों के विचार मांगेगा।
- (v). पिछले 12 महीनों में लाइसेंस करार में यथा शामिल किए गए कार्यनिष्पादन मानकों को प्राप्त नहीं करने वाले लाइसेंसधारी के मामले में, टीएएमपी आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क अधिसूचित करने के लिए प्रस्ताव पर विचार नहीं करेगा और लाइसेंसधारी आगामी वित्तीय वर्ष के लिए लागू सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क के लिए ही हकदार होगा।
- (vi). महापत्तन न्यास के मतों पर विचार करते हुए, यदि टीएएमपी संतुष्ट होता है कि रियायत करार में यथा शामिल किए गए कार्यनिष्पादन मानक अर्जित कर लिए गए हैं, तो आगामी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से लागू किए जाने वाले 15 मार्च तक कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क अधिसूचित करेगा।
- (vii). कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क के लिए प्रस्ताव पर विचार करते समय, टीएएमपी कार्यनिष्पादन मानकों और लाइसेंसधारी द्वारा इसके पालन का ध्यान रखेगा। टीएएमपी लाइसेंसधारी द्वारा कार्यनिष्पादन मानकों की उपलब्धि अथवा अन्यथा के आधार पर कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क प्रस्ताव स्वीकृत अथवा खारिज करने पर निर्णय करेगा। सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क और कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क का निर्धारण 2013 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के साथ संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये गए उदाहरण का अनुसरण करेगा।
- (viii). परिचालन के तीसरे वर्ष से, लाइसेंसधारी से कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क प्रस्ताव स्वतंत्र अभियंता द्वारा यथा प्रमाणित पिछले 12 महीनों की अवधि में कार्यनिष्पादन मानकों की उपलब्धि के अधीन टीएएमपी द्वारा स्वतः ही अधिसूचित किया जाएगा। लाइसेंसधारी, तीसरे वर्ष से आगे कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क के लिए, स्वतंत्र अभियंता से उपलब्धि प्रमाणपत्र के साथ कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क प्रस्ताव 1 मार्च तक जमा करेगा और टीएएमपी आगामी वित्तीय वर्ष से लागू होने वाले कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क 20 मार्च तक अधिसूचित करेगा।

अनुबंध-II**सीपोर्ट शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड****कार्यनिष्पादन मानक**

सीपोर्ट शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड निम्नलिखित दोनों कार्यनिष्पादन मानकों को पूरा करेगा:

- (क). न्यूनतम गारंटीशुदा उपलब्धता 90 प्रतिशत प्रति बिजली से चलने वाला मोबाइल रबड़ टायर वाला होपर प्रतिमाह है,
- (ख). लाइसेंसधारी एक होपर का इस्तेमाल करते हुए बारह मिनटों में 40 टन क्षमता के एक ट्रक को भरेगा, यदि ट्रक उतराई के लिए उपलब्ध हों।

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**NOTIFICATION**

Mumbai, the 22nd October 2019

No.TAMP/25/2019-VOCPT In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes the proposal received from the Seaport Shipping Pvt. Ltd. (SSPL) for notification of its Scale of Rates for Design, Supply, Installation, Testing, Commissioning and Maintenance of Mobile Rubber Tyred electrically operated hoppers for a period of 10 year on revenue share basis in the name of the Operator viz. SSPL as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**Case No.TAMP/25/2019-VOCPT****Seaport Shipping Private Limited**

...

Applicant**QUORUM:**

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER(Passed on this 10th day of October 2019)

This case relates to the proposal received from the Seaport Shipping Pvt. Ltd. (SSPL) for notification of its Scale of Rates (SOR) for Design, Supply, Installation, Testing, Commissioning and Maintenance of Mobile Rubber Tyred electrically operated hoppers for a period of 10 year on revenue share basis in the name of the Operator viz. SSPL.

2. This Authority vide its Order No.TAMP/60/2016-VOCPT dated 16 December 2016, approved the Cargo handling charges for evacuation of cargo through Mobile Rubber Tyred Electrically operated 120T Hopper at Berth Nos.III and IV under the Reference Tariff Guidelines of 2013 issued by the Ministry of Shipping (MOS).

3.1. The SSPL vide its letter dated 08 May 2019 has intimated that V. O. Chidambaranar Port Trust (VOCPT) granted License for the above said project for a period of 10 years under revenue sharing model as per the License Agreement. The commercial operation of the Hoppers commenced on 13 April 2018. Since then they have been paying the monthly revenue share to the port regularly.

3.2. The SSPL vide its letter dated 8 May 2019 has also submitted a proposal for notification of SOR in the name of SSPL for the rate to be charged from 01 April 2019. The main submissions made by SSPL regarding Cargo Handling Charges through Hopper are as under:

- (i). The tariff caps will be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 01 January 2016 and 01 January of the relevant year. Such automatic adjustment of tariff caps will be made every year and the adjusted tariff caps will come into force from 01 April of the following year.
- (ii). TAMP, as per the Clause 2.8 and 2.9 of the Tariff Policy, 2018, has approved the Indexation factor of 2.56% on the existing SOR for the year 2019-20 vide its letter No.TAMP/12/2019-Misc dated 29 March 2019.
- (iii). In accordance with the above referred letter, the SSPL has requested this Authority to approve the following indexed rate by applying 2.56% indexation factor on the Reference Tariff approved in December 2016 Order:

Commodity	Rate per MT (in ₹)	
	Foreign	Coastal
Dry Bulk Cargo	16.97	10.18

3.3. The SSPL has enclosed a copy of VOCPT letter dated 03 December 2018 to its proposal wherein the VOCPT has stated that M/s. SSPL has deployed 8 Nos. of Mobile rubber tyred electrically operated hoppers at VOCPT for handling dry bulk cargoes on license basis under revenue share model. The said letter of the VOCPT states that hoppers started operation from 13 April 2018 and performance is found to be satisfactory. However, the flex-flap system to control the dust emission is yet to be installed in 7 out of 8 hoppers.

3.4. Thus the SSPL has requested to issue necessary Notification for proposed SOR in its name, for the year 2019-20 commencing from 01 April 2019 for cargo handling charges for handling through hopper to enable SSPL to collect the same from the users from 01 April 2019.

4. The SSPL vide its email dated 14 May 2019 has also furnished the draft SOR and Performance Standards.

5.1. On perusing the proposed SOR, it was observed that the indexation factor applied by the SSPL was not correct. In view of the above, the SSPL was requested to furnish the corrected SOR alongwith following information immediately, vide our letter dated 12 June 2019.

- (i). Since the SSPL has commenced the commercial operation from 13 April 2018, correct annual indexation for the base year 2016 will be the indexation factor announced for the year 2017-18, which is 1.20%.

Applying the said indexation the rate shall be as follows:

Base Rate approved in Order No. TAMP/60/2016-VOCPT dated 16 December 2016 for Dry Bulk Cargo (Per MT) (In ₹)		Indexed Rate Applying 1.2% for the year 2017-18 and Nil for the year 2018-19 (From 1.4.2018 to 31.7.2018) (Per MT) (In ₹)		Applicable for the part of the year 2018-19
Foreign	Coastal	Foreign	Coastal	
16.21	9.73	16.40	9.84	13.4.2018 (commencement of operation) to 31.7.2018

- (ii). The annual indexation for the remaining part of the year 2018-19 i.e. from 01 August 2018 to 31 March 2019 and subsequent years shall be increased automatically in view of note prescribed in the SOR in this regard notified in the name of SSPL. Accordingly the rate shall be as follows (This is for information of SSPL as regards application of automatic indexation):

Year	Indexation factor announced by this Authority	Indexed Rate Per MT (In ₹)	
		Foreign	Coastal
2018-19 (From 01.08.2018 to 31.03.2019)	2.07%	16.73	10.04
2019-20	2.56%	17.15	10.29

- (iii). Indicate the tariff arrangement under which SSPL has collected tariff for the period from commencement of operation i.e. from 13 April 2018 to 31 March 2019.

- (iv). Furnish the reason for not submitting the completion certificate from Independent Engineer.

- (v). Furnish the SOR (at the base rate) alongwith conditionalities as approved in the tariff Order No.TAMP/60/2016-VOCPT.

5.2. In response, the SSPL vide letter dated 18 June 2019 has stated that under the License Agreement, no independent Engineer was appointed by the licensor, viz. VOCPT and hence Completion Certificate from Independent Engineer is not applicable for this project. As far as SOR along with conditionalities in concerned, SSPL has stated that the same is already submitted vide their email dated 14 May 2019.

6. A copy each of the proposal of SSPL dated 8 May 2019 and 18 June 2019 was forwarded to VOCPT for its comments, followed by reminders dated 28 June 2019 and 05 July 2019. The VOCPT has responded vide its email dated 17 July 2019. Submissions of VOCPT are summarised below:

The project commenced from 13 April 2018. As per the terms and conditions of license agreement independent Engineer is not required to issue Completion Certificate for the subject project. Committee comprising Port Officers inspected the work and submitted the report. Based on the report, completion certificate dated 03 December 2018 was issued (Copy enclosed). The firm has requested to grant time up to September 2019 for installing the flex flap system.

The proposal of SSPL, may be considered to notify the SOR for the subject project in the name of M/s. Seaport Shipping Pvt. Ltd.

7.1. Clause 2.9.1 of the Tariff Guidelines of 2008 for fixation of upfront tariff stipulates that the private operator shall approach this Authority for notification of SOR containing ceiling rates applicable to his operations before commencement of commercial operations as required under Section 48 of MPT Act and as per Clause 2.9.2. of tariff guidelines of 2008, the SOR to be framed by this Authority shall be in line with the tariff caps prescribed for the port and included in the bid document subject to indexation explained in Clause 2.8. Such SOR and statement of conditions shall be notified by this Authority in the Gazette of India as required by the Major Port Trusts Act, 1963.

7.2. While clause 2.9.1 of the Upfront Tariff Guidelines of 2008 explicitly stipulates that before commencement of commercial operation, the private operator shall approach this Authority for notification of the SOR as required under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963, no such an explicit provision is stipulated in the Tariff Guidelines of 2013.

7.3. As per Section 48 read with Section 42(4) of the Major Port Trusts (MPT) Act, 1963, any person authorised by the Major Port Trusts to render services can levy tariff based on the SOR notified by this Authority. That being so, the BOT operators governed under the tariff guidelines 2013 who have been authorised by Major Port Trust under Section

42(3) of the MPT Act 1963, need to get the indexed SOR notified in their name well before the commencement of operations.

7.4. As per clause 4.2 of the Reference Tariff Guidelines of 2013, the Tariff Caps are to be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in WPI occurring between 1 January 2008 and 1 January of the relevant year, and the adjusted tariff will come into force from 1 April of the relevant year to 31 March of the following year.

7.5. As per note (i) under 3 General Notes in the reference tariff for transfer of cargo from ship to direct discharge to trucks through mobile rubber tyred electrically operated hoppers on Berth No.III and IV at VOCPT approved by this Authority vide Order No.TAMP/60/2016-VOCPT dated 16 December 2016, tariff caps will be indexed to inflation to an extent of 60% of the variation in the WPI occurring between 1 January 2016 and 1 January of the relevant year.

8. The base year for the reference tariff and the corresponding annual escalation factors for the years 2014-15, 2015-16, 2016-17 and 2017-18 have been announced by this Authority and communicated to all the Major Port Trusts including VOCPT and the same are given below:

Year	Annual Indexation Factor (at 60% of WPI) announced by this Authority under 2013 Guidelines
2014-15	3.78%
2015-16	2.29%
2016-17	NIL
2017-18	1.20%
01.04.18 to 31.07.18	NIL
01.08.18 to 31.03.19	2.07%
2019-2020	2.56%

Thus in short, the SSPL has come up, after commencement of commercial operation on 13 April 2018 for notification of SOR in its name and the VOCPT has also requested to notify the SOR in the name of SSPL from the date of commencement of commercial operation i.e. 13 April 2018.

9.1. With reference to the totality of information collected during the processing of this case, the following position emerges:

- (i). This Authority has passed an Order No.TAMP/60/2016-VOCPT dated 16 December 2016 fixing reference tariff based on the proposal filed by the V. O. Chidambaranar Port Trust (VOCPT) for transfer of cargo from ship to direct discharge to trucks through mobile rubber tyred electrically operated hoppers on Berth No.III and IV in VOCPT. The said order was notified in the Gazette of India Extraordinary on 12 January 2017 vide Gazette No.13.
- (ii). The VOCPT has awarded the said project on license basis for a period of 10 years to M/s. Seaport Shipping Pvt. Ltd. (SSPL) and VOCPT has entered into a License Agreement with SSPL on 05 April 2017 for a period of 10 years.
- (iii). As per Section 48 read with Section 42(4) of the Major Port Trusts (MPT) Act, 1963, any person authorised by the MPTs to render services can levy tariff based on the Scale of Rates (SOR) notified by this Authority. That being so, the BOT operators governed under the tariff guidelines 2013 who have been authorised by Major Port Trust under Section 42(3) of the MPT Act 1963, need to get the indexed SOR notified in their name well before the commencement of operations. The SSPL has approached this Authority with a request to notify the SOR in its name, after commencement of commercial operation on 13 April 2018.
- (iv). As reported by the SSPL, the operator has commenced commercial operations with effect from 13 April 2018. A copy of the VOCPT letter dated 03 December 2018 forwarded by the SSPL states that the hoppers started the operations from 13 April 2018 and performance is found satisfactory. The VOCPT has stated that as per terms and conditions of license agreement, a Committee comprising of Port officials has inspected the 8 hoppers deployed by the SSPL and has found that the performance is satisfactory. The flex flap system to control the dust emission was expected to be installed by September 2019. The Port has confirmed that, licensee commenced the operation on 13 April 2018. The VOCPT has categorically stated that since the system is used for operation from 13 April 2018, the effective date of tariff to be notified by this Authority needs to be considered accordingly from 13 April 2018.
- (v). The SSPL in its proposal has sought notification of SOR from 1 April 2019. If reference tariff is notified from 1 April 2019, the tariff collected by SSPL from the date of commencement of operations i.e. from 13 April 2018 till 31 March 2019 will not have any approval of this Authority. As per the

statute, the operator authorised by the port can collect the tariff for services rendered by him only upon notification of SOR by this Authority. The SSPL did not approach this Authority in April 2018 for notification of SOR in their name. It is now, in May 2019 SSPL has filed the proposal with draft SOR for notification of SOR in its name. However, the VOCPT has categorically stated that since the system is used for operation from 13 April 2018, the effective date of tariff to be considered accordingly i.e. 13 April 2018. That being so, this Authority is inclined to entertain the proposal of SSPL for notification of the SOR taking the reference tariff approved in the Order dated 16 December 2016 subject to the applicable WPI escalation announced by this Authority. In view of the position brought out above, and as recommended by the Licensor port, the indexed SOR notified by this Authority shall come into effect from the date the SSPL commenced the operations i.e. from 13 April 2018.

- (vi). (a). With reference to the indexation of the reference tariff fixed vide Order dated 16 December 2016, it is noteworthy that the SSPL, while filing of its draft SOR, has applied the escalation factor of 2.56% which was announced by this Authority for the year 2019-20. In this regard, it is relevant to mention that para 11(xiii) of the reference tariff Order passed by this Authority vide Order No.TAMP/60/2016-VOCPT dated 16 December 2016 and the General Note no.(i) in the SOR approving the reference tariff, states that the tariff cap is to be indexed to inflation to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1 January 2016 and 1 January of the relevant year. The general note explicitly states the base year for WPI escalation has to be 1 January 2016.
- (b). That being so, the applicable escalation factor to arrive at the indexed SOR as on 13 April 2018 is 1.2% for the year 2017-18; Nil for the period 1 April 2018 to 31 July 2018 and 2.07 for the period 1 August 2018 to 31 March 2019. Further, for ease of application and since the year 2019-20 has also commenced, the indexed rate applicable for the year 2019-20 applying the applicable indexation factor of 2.56% is also prescribed in the SOR notified in the name of the SSPL. For the subsequent years, the tariff shall be indexed automatically applying the indexation factor @ 60% of the WPI with the base year as of January 2019 to be announced by this Authority annually under the Reference Tariff Guidelines of 2013. The General note no.(i) to Schedule (2) proposed by SSPL as regards automatic escalation in the tariff prescribed in the general note approved in the Order dated 16 December 2016 is, therefore, slightly modified to that extent.

Accordingly, applying the correct indexation factor announced by this Authority, the indexed tariff notified in the name of SSPL is as follows:

Rate / MT (in ₹)					
From 13 April 2018 to 31 July 2018.		From 1 August 2018 to 31 March 2019.		For the year 2019-20	
Indexed Rate Applying 1.2% for the year 2017-18 and Nil for the year 2018-19 (From 1.4.2018 to 31.7.2018) (per MT in ₹)		Indexed Rate to be applicable from 1 August 2018 to 31 March 2019 applying 2.07% indexation factor		Indexed Rate Applying 2.56% indexation	
Foreign	Coastal	Foreign	Coastal	Foreign	Coastal
16.40	9.84	16.74	10.05	17.17	10.30

- (vii). All the other conditionalities governing the application of the rates as approved in the SOR of the Order dated 16 December 2016 are retained subject to the following:

This Authority, has passed an Order No.TAMP/53/2015-VOCPT dated 29 September 2015 based on the recommendations of Directorate General (DG) Shipping on the clarification sought by the VOCPT regarding levy of concessional charges for coastal cargo / container. The provisions approved in the said Order were further amended vide Order No.TAMP/53/2015-VOCPT dated 26 November 2015. The said Order passed is for common adoption by all the Major Port Trusts. Subsequent to the said Order, the DG Shipping vide its letter no.SD-9CHART(309)/2016 dated 20 May 2016 has issued further clarification on the provision approved in the 26 November 2015 Order. This Authority has accordingly passed a clarificatory Order slightly amending the provision prescribed in para 9A(ii) and 10(ii) of the Order dated 26 November 2015. The amended provisions approved by this Authority in the said Order which are found relevant in the case of SSPL as regards cargo handling charges have been updated accordingly, in the SOR of SSPL as note no.(ii) in place of proposed note no.(ii) under General terms and conditions. Further, general conditionalities regarding applicability of Coastal Concession for ship to shore and shore to yard movement excluding few cargo items not entitled for

Coastal Concession are prescribed. This is in line with the Coastal Concession Policy of the Government and is prescribed uniformly in the SOR of all Major Port Trusts and BOT Operators.

9.2. In the result, and for the reasons given above and based on collective application of mind, this Authority approves notification of the SOR and Performance Standards for the transfer of cargo from ship to direct discharge to trucks through mobile rubber tyred electrically operated hoppers on Berth No.III and IV on license basis for a period of 10 years basis in the name of SSPL operating at VOCPT attached as **Annex-I** and **II** respectively.

9.3. The SOR notified for SSPL shall be deemed to have come into force from the date of commencement of operations by SSPL at VOCPT i.e. from 13 April 2018.

9.4. During the commercial operation at the terminal, within 15 days from the end of every quarter, the SSPL is directed to submit to this Authority through the VOCPT a report containing the physical performance during the preceding three months and at the end of each year to submit a report containing physical and financial performance within two months of closure of the financial year.

9.5. As per clause 3.8.5 of the guidelines, if any question arises requiring clarifications or interpretation of the SOR and the statement of conditionalities, the matter shall be referred to this Authority and its decision in this regard will be binding on the operator.

9.6. The Licensee is expected to perform at least at the performance norms brought out in the bid document/ License agreement.

9.7. The actual performance of the Licensee will be monitored by this Authority. If any complaint regarding quality of service is received, this Authority may enquire into such allegation and forward its findings to the VOCPT. If any action is to be taken against the operator, the VOCPT shall initiate appropriate action in accordance with the provisions of the relevant License Agreement.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.- III/4/Exty./264/19]

Annex-I

SEAPORT SHIPPING PRIVATE LIMITED

Scale of Rates for transfer of cargo from ship to direct discharge to trucks through mobile rubber tyred electrically operated hoppers on Berth No. III and IV at V.O.Chidambaranar Port Trust.

CHAPTER 1 – DEFINITIONS & GENERAL TERMS & CONDITIONS

1.1. DEFINITIONS – GENERAL

In this Scale of Rates, unless the context otherwise requires, the following definitions shall apply:

- (i). **“Coastal Vessel”** shall mean any vessel exclusively employed in trading between any Terminal or place in India to any other Terminal or place in India having a valid coastal license issued by the Competent Authority / Director General of Shipping.
- (ii). **“Foreign-going Vessel”** shall mean any vessel other than a coastal vessel.
- (iii). **“Port”** shall mean V.O. Chidambaranar Port Trust.
- (iv). **“Shift”** shall mean shift of eight hours as applicable to Port employees.
- (v). **“Per day”** shall mean a calendar day or part thereof.
- (vi). **“TAMP”** shall mean the Tariff Authority for Major Ports constituted under Section 47A of the Major Port Trusts Act, 1963.
- (vii). **“Tonne”** shall mean one Metric Tonne or 1000 Kilograms.

1.2. General Terms & Conditions

- (i). The status of the vessel, as borne out by its certification by the Customs or the Director General of Shipping, is the relevant factor to decide whether vessel is 'coastal' or 'foreign-going' for the purpose of levy of vessel related charges and the nature of cargo or its origin will not be of any relevance for this purpose.

- (ii). Criteria for levy of vessel related charges (VRC) at Concessional Coastal rate and foreign rate
 - (a) In cases of such conversion, coastal rates shall be chargeable by the load port from the time the vessel starts loading coastal goods.
 - (b) In cases of such conversion coastal rates shall be chargeable till the vessel completes discharging operations at the last call of Indian Port; immediately thereafter, foreign going rates shall be chargeable by the discharge ports.
 - (c) For dedicated Indian coastal vessels having a Coastal licence from the Director General of Shipping, no other document will be required to be entitled to coastal rates.
- (iii). Criteria for levy of Cargo Related Charges (CRC) at Concessional Coastal rate
 - (a) Foreign going Indian vessel having General Trading License issued for 'worldwide and coastal' operation should be accorded applicable coastal rates with respect to Handling Charges (HC) i.e. ship to shore transfer and transfer from/ to quay to/ from storage yard including wharfage in the following scenario:-
 - (i). Converted to coastal run and carrying coastal cargo from any Indian Port and destined for any other Indian Port.
 - (ii). Not Converted* to coastal run but carrying coastal cargo from any Indian Port and destined for any other Indian Port.

*The Central Board of Excise & Customs - Circular No 15/2002-Cus dated 25th February 2002 allows carriage of coastal cargo from one Indian Port to another Indian Port in India, in Indian flag foreign going vessels without any Custom Conversion.
 - (b). In case of a Foreign flag vessel converted to coastal run on the basis of a License for Specified period or voyage issued by the Director General of Shipping, and a Custom Conversion Order, the coastal cargo/ container loaded from any Indian Port and destined for any other Indian Port should be levied at the rate applicable for coastal cargo/ container.
- (iv).
 - (a). The cargo related charges for coastal cargo other than thermal coal should not exceed 60% of the normal cargo related charges.
 - (b). In case of cargo related charges, the concessional rates should be levied on all the relevant handling charges for ship shore transfer and transfer from/to quay to/from storage yard including wharfage.
 - (c). Cargo from a foreign port which reaches an Indian Port "A" for subsequent transshipment to Indian Port "B" will be levied the concession charges relevant for its coastal voyage. In other words, cargo from/to Indian Ports carried by vessels permitted to undertake coastal voyage will qualify for the concession.
- (v). Interest on delayed payments/refunds.
 - (a). The user shall pay penal interest on delayed payments of any charge under this Scale of Rates. The rate of interest will be (prescribed at 2% above the Prime Lending Rate of State Bank of India)
 - (b). Likewise, the Terminal shall pay penal interest on delayed refunds. The rate of interest will be (prescribed at 2% above the Prime Lending Rate of State Bank of India)
 - (c). The delay in refunds will be counted beyond 20 days from the date of completion of services or on production of the documents required from the users, whichever is later. (The Terminal must specify specific documents to be submitted for claiming refund).
 - (d). The delay in payments by the users will be counted beyond 10 days after the date of raising the bills by the Terminal. This provision shall, however, not apply to the cases where payment is to be made before availing the services as stipulated in the Major Port Trusts Act, 1963 and/or where payment of charges in advance is prescribed in this Scale of Rates.
- (vi). All charges worked out shall be rounded off to the next higher rupee on the grand total of each bill.
- (vii). No claims for refund shall be entertained unless the amount refundable is `100/- or more. Likewise, operator shall not raise any supplementary or under charge bills, if the amount due to operator is `100/- or less.

- (viii). (a). The rates prescribed in this Scale of Rates are ceiling levels; likewise, rebates and discounts are floor levels. The operator may, if he so desires, charge lower rates and/ or allow higher rebates and discounts.
- (b). The operator may also, if he so desires, rationalize the prescribed conditionalities governing the application of rates prescribed in the Scale of Rates if such rationalization gives relief to the user in rate per unit and the unit rates prescribed in the Scale of Rates do not exceed the ceiling levels. Provided that the operator should notify the public such lower rates and /or rationalization of the conditionalities governing the application of such rates and continue to notify the public any further changes in such lower rates and/ or in the conditionalities governing the application of such rates provided the new rates fixed shall not exceed the rates notified by the TAMP.
- (ix). User will not be required to pay charges for delays beyond a reasonable level attributable to operator.

2. **CARGO HANDLING CHARGES FOR EVACUATION OF CARGO THROUGH MOBILE RUBBER TYRED ELECTRICALLY OPERATED 120T HOPPER AT BERTH NO. III and IV:**

Rate per in MT (in ₹)

Sl. No.	Commodity	Rate from date of commencement of operations i.e. from 13 April 2018 to 31 July 2018		Rate from 01 August 2018 to 31 March 2019		Rate for the year 2019-20	
		Foreign	Coastal	Foreign	Coastal	Foreign	Coastal
1	Dry Bulk Cargo	16.40	9.84	16.74	10.05	17.17	10.30

Notes:-

Rate prescribed above is for transfer of cargo from ship to direct discharge to trucks through mobile rubber tyred electrically operated hoppers on Berth No. III and IV.

3. **GENERAL NOTES:**

- (i). The tariff caps will be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1 January 2019 and 1 January of the relevant year. Such automatic adjustment of tariff caps will be made every year and the adjusted tariff caps will come into force from 1 April of the relevant year to 31 March of the following year. The next automatic indexation in tariff will be from 01 April 2020.
- (ii). From the date of Commercial Operation (CoD) till 31st March of the same financial year, the tariff would be limited to the indexed Reference Tariff relevant to that year, which would be the ceiling. The aforesaid Reference Tariff shall be automatically revised every year based on an indexation as provided in para 2.2 of the tariff guidelines of 2013 which will be applicable for the entire licence period.
- However, the Licensee would be free to propose a tariff along with Performance Standards (the "Performance Linked Tariff") from the second year of operation onwards, over and above the indexed Reference Tariff for the relevant financial year, at least 90 days before the 1st April of the ensuing financial year. Such Performance Linked Tariff shall not be higher than 15% over and above the indexed Reference Tariff for that relevant financial year (and this will be the Tariff Cap). The Performance Linked Tariff would come into force from the first day of the following financial year and would be applicable for the entire financial year.
- (iii). The proposal shall be submitted to TAMP along with a certificate from the independent engineer appointed under the Concession Agreement of the Project indicating the achievement of Performance Standards in the previous 12 months as incorporated in the Licence Agreement or for the actual number of months of operation in the first year of operation as the case may be.
- (iv). On receipt of the proposal, TAMP will seek the views of the Major Port Trust on the achievement of Performance Standards as outlined in para 5 of the tariff guidelines of 2013, within 7 days of receipt.
- (v). In the event of Licensee not achieving the Performance Standards as incorporated in the Licence Agreement in previous 12 months, TAMP will not consider the proposal for notifying the Performance

Linked Tariff for the ensuing financial year and the Licensee shall be entitled to only the indexed Reference Tariff applicable for the ensuing financial year.

- (vi). After considering the views of the Major Port Trust, if TAMP is satisfied that the Performance Standards as incorporated in the Concession Agreement have been achieved, it shall notify the performance linked tariff by 15th of March to be effective from 1st of April of the ensuing financial year.
- (vii). While considering the proposal for Performance Linked Tariff, TAMP will look into the Performance Standards and its adherence by the Licensee. TAMP will decide on the acceptance or rejection of the Performance Linked Tariff proposal based on the achievement or otherwise of the Performance Standards by the Licensee. Determination of indexed Reference Tariff and Performance Linked Tariff will follow the illustration shown in the Appendix attached to the tariff guidelines of 2013
- (viii). From the third year of operation, the Performance Linked Tariff proposal from the Licensee shall be automatically notified by TAMP subject to the achievement of Performance Standards in the previous 12 months period as certified by the Independent Engineer. The Licensee, for the Performance Linked Tariff from the third year onwards, will submit the Performance Linked Tariff proposal along with the achievement certificate from the independent engineer by 1st March and TAMP shall notify by 20th March, the Performance Linked Tariff to be effective from the ensuing financial year.

Annex-II

SEAPORT SHIPPING PRIVATE LIMITED

PERFORMANCE STANDARDS

The Seaport Shipping Private Limited shall meet both the following Performance Standards:

- (a). The Minimum guaranteed availability is 90% per mobile rubber tyred electrically operated hopper per month,
- (b). The Licensee shall fill one truck of 40T capacity in twelve minutes using one hopper, if the trucks are available for unloading.